(b) No, Sir Under the scheme only a small quantity left ever after procurement of the marketed surplus will be allowed to be retained by the growers and retailers.

(c) The procurement prices per quintal of wheat are Rs. 82.00 for specified superior varieties, Rs. 71.00 to Rs. 74.00 for red indigenous and Rs. 76.00 for other varieties. The issue price for superior varieties is being fixed shortly. For other varieties present issue price fixed is Rs. 78.00 per quintal

(d) The procurement prices are always fixed so as to be remunerative to the producers.

Acute Housing Problem of Government Servants on Transfer

*579. SHRI D. B. CHANDRA GOWDA: Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state:

(a) whether when Government servants are transferred from one place to another, they face acute housing problem; and

(b) if so, what steps Government have taken in this regard?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING (SHRI BHOLA PASWAN SHASTRI): (a) Yes, Sir, sometimes.

(b) There is no proposal for giving special consideration for allotment of accommodation from the general pool to officers transferred from one station to another. They have to wait for their turn for allotment of accommodation in the general pool at places of their new posting. In the case of IAS and IPS officers, who are on State Cadres and are required to man Central Government posts at Delhi/New Delhi, a separate pool known as 'Tenure Officers' Pool' has been created.

किसानों के लिए इस्पात के सस्ते कृषि उपकरण उपलब्ध कराने सम्बन्धी योजनायें

*580. **श्री नाथूराम अहिरवार :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात से बने कृषि उपकरणों के मूल्यों में वृद्धि हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या किसानों को उचित मूल्य पर ये उपकरण उपलब्ध कराने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णा साहिब पी. शिन्दे) : (क) लोह तथा इस्पात के मूल्यों और मजदूरों की मजदूरी में वृद्धि के परिणामस्वरूप कृषि उपकरणों के मूल्यों में वृद्धि हुई है ।

(ख) भारत सरकार ने कृषि उपकरणों के प्रचलन और किसानों को उचित दरों पर उनकी पूर्ति के लिये कई उपाय किये हैं । ये उपाय नीचे दिये गये हैं :—

1. तीसरी योजना की अवधि में विभिन्न राज्यों में कृषकों को 25 प्रतिशत से 33 प्रतिशत की साहाय्य दरों पर सुधरे हुये उपकरण बेचे गये थे, ताकि उन्हें लोकप्रिय बनाया जा सके । इस सहायता का 25 प्रतिशत भाग केन्द्रीय सरकार ने वहन किया था ।

2. विशेषकर सरकारी क्षेत्र की यूनिटों में कृषि उपकरणों के विनिर्माण में तेजी लायी जा रही है । इन यूनिटों से उत्पादन बढ़ाने के लिये कहा गया है, ताकि उनके द्वारा निर्मित उपकरण कृषकों को उचित मूल्य पर बेचे जा सकें ।

3. विभिन्न प्रकार के कृषि कार्यों के लिये कृषकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये देश में सुधरे हुये